[2010] 8 एस. सी. आर. 794

धन सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 488/2009)

जुलाई 22, 2010

[डॉ बी. एस. चौहान और स्वतंत्र कुमार, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एस. एस. 148, 149, 323, 506, 452 और 304 (भाग II)-मृतक और उसके भाई के बीच संपत्ति पर विवाद-मृतक के भाई और अपीलार्थी सहित आरोपियों ने मृतक पर हमला किया-अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया-अन्य आरोपियों ने भी मृतक और उसकी पत्नी को चोटें पहुंचाई-डॉक्टर ने पुष्टि दर्ज की कि मृतक कथन देने के लिए फिट था-हेड कांस्टेबल द्वारा कथन दर्ज किया गया-धारा 323 के तहत मामला दर्ज किया गया-कुछ दिनों के बाद अस्पताल में मृतक की मौत हो गई-मामले को धारा 302 के तहत तब्दील किया गया-मृतक के कथन को मृत्युकालीन कथन के रूप में माना गया-घोषणा के आधार पर धारा 302 के तहत दोषसिद्धि-चुनौती-अभिनिर्णितः मृत्युकालीन कथन स्पष्ट और संतोषजनक थे और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से

पुष्टि की गई थी-हालांकि पत्नी और मृतक की बेटी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया, लेकिन, यह अपने मृतक के आप से, अभियोजन के मामले को दुर्बल नहीं करेगा-मृतक के पास अपने भाई और अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था-इस प्रकार, अभियोजन ने अपीलार्थी के दोष को साबित करने में सफलता प्राप्त की- हालाँकि, सामूहिक विश्लेषण और सबूतों की जांच से पता चला कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का कोई आशय नहीं था और उसने उसे मारने के आशय से या इस ज्ञान के साथ वार नहीं किया कि इससे मौत होने की संभावना थी। इन परिस्थितियों में, दोषसिद्धि धारा 302 से बदलकर धारा 304 (भाग II) कर दी गई साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 32 गवाह पक्षद्रोही गवाह ।

794 धन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 795

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 32-मृत्युकालीन कथन-हेड कांस्टेबल द्वारा पीड़ित का कथन दर्ज किया गया-पीड़ित की कुछ दिनों के भीतर मृत्यु हो गई-कथन की मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राहयता- अभिनिर्णितः धारा 32 (1) के संदर्भ में, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या ऐसी परिस्थितियों के बारे में दिया गया कथन ग्राह्य है। धारा 32 के प्रावधान के अनुसार यह अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है कि मृत्युकालीन कथन को किसी नामित या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए-डॉक्टर ने घोषणा की कि पीड़िता कथन देने के लिए फिट है-पीड़ित के निकटतम

रिश्तेदार ने बयानों को समर्थित किया-ऐसे कथन तथ्यों और परिस्थितियों में ग्राह्य हैं दंड संहिता, 1860-एस.एस. 148, 149, 323, 506, 452 और 304 (भाग-2)-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 162 (2) ।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक का अपने भाई के साथ एक आवासीय मकान को लेकर विवाद था। घटना के दिन, मृतक, उसकी पत्नी (पीडब्लू-3) और उसकी बेटियाँ घर में मौजूद थीं। मृतक के भाई और अपीलार्थी सहित आरोपी घर में घुस आए। अपीलार्थी के हाथ में लोहे की रॉड थी और उसने उसी से मृतक के सिर पर वार किया। मृतक के भाई ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों पर लाठी से प्रहार किया। दूसरे आरोपी ने भी उसकी पीठ पर लाठियां मारीं। पीडब्लू- 3 को भी चोटें आईं। इसके बाद आरोपी भाग गये। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पीडब्लू-8, हेड कांस्टेबल को घटना के बारे में सूचित किया गया। पीडब्लू 8 अस्पताल पहुंचा और मृतक के कथन (एक्स.पीई 1) दर्ज किये। कथन के आधार पर धारा 148, 452, 323, 506 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। करीब एक सप्ताह बाद मृतक की अस्पताल में मौत हो गई। मामले को आईपीसी की धारा 302 के तहत तब्दील किया गया। विचारणीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सिर पर लगी चोट का आरोप जो अपीलार्थी पर लगाया गया था, मृतक की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी और मामला धारा 300 के खंड "तीसरे" के अंतर्गत

आता है और तदनुसार अपीलार्थी को धारा 148, 149, 323, 506, 452 और 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट ने विचारणीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

तत्काल अपील में, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि हेड कांस्टेबल द्वारा दर्ज किया गया कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था; मृतक के बेटे और बेटी को गवाह के रूप में परीक्षित नहीं करवाया गया और निष्कर्ष बिना किसी सबूत के आधारित थे और विकृत थे; या इसके अलावा, सजा आईपीसी की धारा 304 (भाग II) आईपीसी के तहत होनी चाहिए थी न कि धारा 302 आईपीसी के तहत।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्णित किया

1.1. डॉक्टर, पीडब्लू-1 ने एक्स.पीई 1 पर एक पुष्टि दर्ज की, कि मृतक कथन देने के लिए फिट था और कथन उसे पढ़कर सुनाया गया था और उसके द्वारा कथन सही पाए जाने के बाद, कथन पर उसके हस्ताक्षर व मृतक के बच्चों के भी विधिवत हस्ताक्षर लिए गये थे। केवल तथ्य यह है कि डॉक्टर ने मृतक को कथन देने के लिए फिट घोषित कर दिया था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में मृत्यु का कोई गंभीर खतरा

नहीं था। दरअसल, कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। विचारणीय न्यायालय ने उन तथ्यों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि मृतक ने विशेष रूप से उस भूमिका का उल्लेख किया था जो विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार थी। उनका कथन, मृत्युकालीन कथन के रूप में, अपीलार्थी की भूमिका के बारे में साफ और स्पष्ट था और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से संपुष्टि की गई थी। [पैरा 7] [804-डी-ई; जी-एच; 805-]

1.2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, यह अनिवार्य नहीं है कि किसी नामित या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा मृत्युकालीन कथन दर्ज किया जाए। जांच एजेंसी को अधिनियम की धारा 32 सपठित धारा 162 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ ही साथ कानून और अधिनियम के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मृत्युकालीन कथन दर्ज करते समय स्थापित प्रथा के अनुसार कार्य करना होगा। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी संदेह या झूठे आरोप की संभावना को खत्म करने के लिए ऐसे कथन मजिस्ट्रेट या डॉक्टर द्वारा दर्ज किये जाएंगे। अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या ऐसी परिस्थितियों के बारे में दिया गया कथन ग्राह्य है। मौजूदा मामले के तथ्यों पर कोई संदेह नहीं है कि मृतक का कथन डॉक्टर द्वारा कथन देने

के लिए फिट घोषित गए कथन किए जाने के बाद ही दर्ज किया गया था। मृत्युकालीन कथन का समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि प्रासंगिक समय पर मौजूद मृतक के निकटतम रिश्तेदार ने किया था। एफआईआर स्वयं मृतक के कथन पर दर्ज की गई थी, जिसे हेड कांस्टेबल ने दर्ज किया था, जो संबंधित समय पर ऐसा करने में सक्षम था। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे कथन की ब्राह्मता में कोई कानूनी कमजोरी नहीं है। [पैरा 7] [806 सी एच 806 ए]

दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 4 एससीसी 332- पर आश्रित।

चेरलोपल्ली चेलिमिनाबी साहेद बनाम एपी राज्य (2003) 2 एससीसी 571; कांति लाल बनाम. राजस्थान राज्य (2004) 10 एससीसी 113-डिस्टींगविशड।

राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार (1985) 4 एससीसी 476 रेफर्ड।

धन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 797

2.1. मृतक और उसके भाई के बीच विवाद चल रहा था। मृतक की मौत के बाद परिवार ने अपना विवाद सुलझा लिया है। अभियोजन पक्ष ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया कि मृतक के बेटे और बेटी को अभियोजन

द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया, क्योंकि उन्हें आरोपियों द्वारा मना लिया गया था। पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4, मृतक की पत्नी और बेटी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित हुए । लेकिन, यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को दुर्बल नहीं करेगा। न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और अभियोजन किसी भी उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम है, तो न्यायालय को तथ्य की परवाह किए बिना दोषी को दंडित करना चाहे कुछ गवाह पक्षद्रोही घोषित हों चुके हों। [पैरा 8] [806- एच 807-ए-डी]

2.2. मृतक के पास झूठा कथन देने का कोई कारण नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि लोहे की रॉड से उसके सिर पर बहुत जोरदार वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, वह घटना में प्रत्येक आरोपी की भूमिका स्पष्ट करने में सक्षम था। यह एक ऐसा मामला था जहां सिर की चोट घातक साबित हुई जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। जांच अधिकारी सहित अन्य गवाहों के कथन के अनुसार, मृतक की पत्नी और बेटी को चोटें घटना के दौरान और मृतक के घर में लगी थीं। मृतक के पास किसी भी व्यक्ति, विशेषकर उसके भाइयों और अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। मृतक को लगी चोटें पीडब्लू 1 के कथनों से पूरी तरह से

पुष्ट हुई। इन गवाहों और मेडिको लीगल रिपोर्ट पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। केवल, क्योंकि मृतक के परिवार के सदस्य अदालत के समक्ष गलत कथन देना चाहते थे इससे अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष ठोस और उचित सबूतों के साथ आरोपी के अपराध को सामने लाने में सक्षम था। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्षो को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं था। [पैरा 9] [808-ई-एच 809-ए-बी]

जागृति देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2009) 14 एससीसी 771; गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 15 एससीसी 635- का उल्लेख है।

3. यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति मृतक को जान से मारने की नियत से उसके घर गए थे। दरअसल, यह संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद था। अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर एक वार किया। मृतक को मारने का कोई आशय नहीं था, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि आईपीसी की धारा 323 के तहत मामला शुरू में ही दर्ज किया गया था और हेड कांस्टेबल ने पीडब्लू 1, डॉक्टर से परामर्श किया था जिसने मृतक की स्थिति स्थिर बताई थी

और साथ ही साथ प्रमाणित किया गया कि वह कथन देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था, जो अंततः मृत्युकालीन कथन बन गया। रिकॉर्ड पर साक्ष्यों के सामूहिक विश्लेषण और परीक्षण से पता चलता है कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का कोई आशय नहीं था और उसने उसे मारने के इरादे से या इस ज्ञान के साथ वार नहीं किया कि इससे मौत होने की संभावना थी। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी का अपराध धारा 302 से बदलकर आईपीसी की धारा 304 (भाग II) कर दिया जाता है, जिसमें 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 20,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। [पैरा 10, 11] [809 एफ एच 810 ए डी]

केस कानून संदर्भः

(2003) 2 एस. सी. सी. 571 विशिष्ट	पैरा 6,7
(2004) 10 एससीसी 113 विशिष्ट	पैरा 6,7
(1979) 4 एस. सी. सी. 332 उस पर भरोसा करें	पैरा 6
(1985) 4 एस. सी. सी. 476 रेफर्ड	पैरा 6
(2009) 14 एस. सी. सी. 771 रेफर्ड	पैरा 10
(2009) 15 एस. सी. सी. 635 रेफर्ड	पैरा 10

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 488/2009 की ।

आपराधिक अपील संख्या 324 / डीबी / 1999 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2008 से ।

बिसवजीत स्वैन (राजेश प्रसाद सिंह के लिए) अपीलार्थी की ओर से।

बी.एस. मोर (टी.वी. जॉर्ज के लिए) प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

स्वतंत्र कुमार, जे.

1. वर्तमान अपील चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सजा के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2008 के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारणीय न्यायालय के 17 मई 1999 के फैसले की पुष्टि की थी। अपीलार्थी को धारा 148 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा, धारा 452 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दो साल की कठोर कारावास, 1000 /- रुपये जुर्माना और धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए छह महीने की कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000/- रुपये का जुर्माना और इन अपराधों के लिए जुर्माना अदा न करने पर सजा भी दी गई।

धन सिंह वी हरियाणा राज्य 799

2. हम इस मामले में उठने वाले तथ्यों का वर्तमान अपील में उल्लेख कर सकते है। 15.07.1997 को, हेड कांस्टेबल, राम रतन (पीडब्लू 8) सोहना रोड, पलवल पर अपनी पेट्रोल ड्यूटी कर रहे थे, जब शाम लगभग 5 बजे उन्हें सरकारी अस्पताल, पलवल से सूचना (एक्स.पीई) मिली कि तीन व्यक्ति, उक्त अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में शिव राम, बिमला और जय किशन घायल पड़े थे। यह सूचना मिलने पर वह अस्पताल पहुंचे और डॉ. बीएल चिम्पा (पीडब्लू 1) से मिले और उनसे पूछा कि क्या घायल कथन देने के लिए फिट स्थिति में हैं। शाम करीब 6.20 बजे चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय राय एक्स.पी.ई./1 के माध्यम से घायल को कथन देने के लिए फिट घोषित करने के बाद शिव राम का कथन दर्ज किया, जो प्रदर्श पीएफ है। अपने कथन में, शिव राम ने कहा कि उसका अपने भाई खेम चंद के साथ एक आवासीय मकान को लेकर विवाद था। हालाँकि, खेम चंद के पास केवल संपत्ति में हिस्सा था लेकिन उन्होंने पूरे घर में अपना निवास बना रखा था। घटना दिनांक को दोपहर लगभग 2.00 बजे, उसकी पत्नी ओमकली (पीडब्लू 3) और बेटियाँ, बिमला (पीडब्लू 4) और रचना घर में मौजूद थीं और उस समय आरोपी खेम चंद, जय किशन, जय प्रकाश, जगदीश, खेम चंद के बेटे जय भगवान, उनकी पत्नी राज बाला, धन सिंह, देविंदर और राजकली उनके घर में घुस आए और उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। आरोपी धन

सिंह के हाथ में लोहे की रॉड थी और उसने उससे शिव राम के सिर और बाएं कान पर वार किया। आरोपी जय किशन ने उसकी पीठ पर लाठियां मारी और आरोपी जय प्रकाश ने उसके दाहिने हाथ की अंगुलियों पर भी लाठियां मारीं। खेम चंद और राजकली द्वारा उसके कूल्हों और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी लाठियां मारी गई। बिमला को भी लाठियों के यार से चोटें आईं, जिसे बाद में पीडब्लू 4 के रूप में परीक्षित किया गया। घायलों ने शोर मचाया और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग गए और जाते समय उन्होंने घायल व्यक्तियों को धमकी भी दी कि वे अगले अवसर पर उन्हें मार डालेंगे। जांच अधिकारी ने शिव राम, उनकी पत्नी ओमकली और बेटी बिमला की मेडिको-लीगल रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद शिव राम के कथन पीएफ / 1 पर ओमकली और बिमला के समर्थन और हस्ताक्षर भी लिए। इस कथन के आधार पर दिनांक 15.07.1997 को शाम लगभग 6.15 बजे वीरेंद्र सिंह, एएसआई (पीडब्लू 2) द्वारा पुलिस स्टेशन सिटी, पलवल में एफआईआर संख्या 573 अंतर्गत धारा 148, 452, 323 और 506 सपठित धारा 149 दर्ज की गई। एफआईआर को पीएफ/2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

3. अभियुक्तगणों ने मृतक के शरीर पर तथा घायलों पर कुंद हथियार से चोटें पहुंचायी। शिवराम को अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। जांच अधिकारी ने घटना स्थल की रफ साइट योजना तैयार की और दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत गवाहों के कथन दर्ज किए और आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। हालाँकि, इस बीच, शिव राम की हालत गंभीर हो गई और उन्हें सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहाँ अंततः 22 जुलाई, 1997 को

सुबह लगभग 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। एएसआई श्री निवास (पीडब्लू 11) जो उस समय पुलिस पोस्ट, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात थे, ने Inquest कार्यवाही की, जो एक्स पी जे. है। इसके बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो 23 जुलाई, 1997 को डॉ. चंद्र कांत (पीडब्लू 5) द्वारा किया गया। शिव राम की मृत्यु के बाद, उनके बेटे प्रवीण कुमार ने पुलिस स्टेशन सिटी, पलवल में उनकी मौत के बारे में जानकारी दी और हेड कांस्टेबल जगदीश चंद (पीडब्लू 7) ने मामले को आईपीसी की धारा 302 के तहत तब्दील कर दिया और एक विशेष रिपोर्ट एक्स पीके को एरिया मजिस्ट्रेट को भेज दी गई। धारा 302 के तहत मामला दर्ज होने के बाद, मामले की जांच हेड कांस्टेबल से एसआई /एसएचओ पूरन चंद, पीडब्लू 9 ने ले ली और धन सिंह को छोड़कर सभी आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जांच अधिकारी ने विभिन्न गवाहों के कथन दर्ज किये। आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथन प्रदर्श

पीएम से प्रदर्श पीयू तक दिये गये, जिसके परिणामस्वरूप 7 लाठियाँ और 2 डंडा की बरामदगी हुई और जब्ती प्रदर्श पीवी तैयार किया गया। जांच पूरी होने के बाद आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 506, 452 और 302 के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। चूंकि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मामला उसी न्यायालय को सौंपा गया था। इसके बाद सभी नौ आरोपियों पर आरोप पत्र पेश किया गया। आरोपी धन सिंह को फरार अपराधी घोषित कर दिया गया। उसे 18.12.1997 को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अदालत में पूरक चालान पेश किया गया और एक ही घटना से उत्पन्न इन दोनों मामलों को सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ दिया गया। अभियोजन साक्ष्य पूरा होने पर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का कथन दर्ज किया गया। सभी आरोपियों ने अपने बचाव में कोई भी सबूत पेश करने से इनकार कर दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 17 मई 1999 को एक विस्तृत फैसले में यह निष्कर्ष दर्ज किया कि सिर की चोट, जिसके लिए आरोपी धन सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है, शिव राम की मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई गई और उसका मामला आईपीसी की धारा 300 के 'तीसरे' खंड के अंतर्गत आता है। विचारणीय न्यायालय ने दोषसिद्धि के प्रश्न पर अपने निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किए:

"मेरी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि आरोपी राजकली, जय किशन, जगदीश, खेम चंद, जय भगवान, देवेंद्र, राज बाला, जय प्रकाश और बलराम ने धारा 148, 452, 325 और 323 सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध किया है, जबकि आरोपी धन सिंह ने धारा 148, 452, 323 सपठित धारा 149 आईपीसी और धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध किया है। मैं तदनुसार उन्हें दोषी मानता हूं। अब इन अभियुक्तों को सजा पर सुनने के लिए 17 मई 1999 को उपस्थित होने का आदेश दिया गया।"

xxxx xxxx xxxx

धन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 801

[स्वतंत्र कुमार, जे]

4. सत्र न्यायालय के फैसले पर केवल धन सिंह द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से सवाल उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल, 2008 के अपने फैसले में पीडब्लू 5 के कथन पर भरोसा करते हुए माना कि मौत अपीलार्थी को लगी चोटों के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप

करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार वर्तमान अपील दायर करने का अवसर मिला है। अपील केवल अभियुक्त धन सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। अन्य आरोपियों ने विचारणीय न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी।

5. वर्तमान अपील में उठाए गए प्रश्न का निर्धारण करने के लिए आवश्यक संपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, अब हम इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न कानूनी और तथ्यात्मक प्रस्तुतियों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

6. मृत्युकालीन कथन:- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि प्रश्नगत कथन (Ex.PF/1) को मृतक शिव राम के मृत्युकालीन कथन के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, हेड कांस्टेबल राम रतन ने मृत्युकालीन कथन दर्ज नहीं किया होगा और स्थापित प्रथा के अनुसार इसे एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि हेड कांस्टेबल राम रतन द्वारा कथन क्यों दर्ज किया गया था, इसलिए, उक्त कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और इसे अपीलार्थी की सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता है। वकील ने दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1979) 4 एससीसी 332)], चेरलोपल्ली चेलिमिनाबी साहेद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [(2003) 2 एससीसी 571)], राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम लक्ष्मण कुमार [(1985) 4 एससीसी 476)]

और कांति लाल बनाम राजस्थान राज्य [(2004) 10 एससीसी 113] पर भरोसा किया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं था, जो शुरुआत में आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया हो। एफआईआर आईपीसी की धारा 148 452, 323 और 506 सपठित धारा 149 के तहत दर्ज की गई थी, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती थी । यह तथ्य हमारे समक्ष विवादित नहीं है।

7. हेड कांस्टेबल को अस्पताल से सूचना मिली थी और वह अस्पताल गया था जहां उसे पता चला कि तीन घायल व्यक्तियों को किस तरह की चोटें लगी हैं। डॉ. बीएल चिंपा (पीडब्लू 1) ने पूर्व पर एक कथन पीई 1 का समर्थन किया कि उनकी राय में, शिव राम कथन देने के लिए उपयुक्त थे और घायल का कथन उन्हें पढ़कर सुनाया गया था और कथन सही पाए जाने के बाद, कथन पर मृतक व मृतक के बच्चे के विधिवत हस्ताक्षर भी लिए गए थे। 22 जुलाई 1997 को उनकी मृत्यु के बाद, एफआईआर को अन्य धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 302 के तहत तब्दील कर दिया गया और इस तरह की जांच करने के लिए

कानून के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह साक्ष्य में है कि मृतक की हालत सरकारी अस्पताल, पलवल में बिगड़ रही थी, इसलिए, उसे सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मौत की सूचना उनके बेटे प्रवीण कुमार ने थाना सिटी पलवल में दी। केवल यह तथ्य कि डॉक्टर ने शिव राम को कथन देने के लिए फिट घोषित कर दिया था, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में मृत्यु का कोई गंभीर खतरा नहीं था। वास्तव में, कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई । विद्वान विचारणीय न्यायालय ने इन तथ्यों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी गौर किया था कि शिव राम ने विशेष रूप से वह भूमिका बताई थी जो विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार थी। मृत्यु कालीन कथन के रूप में उनका कथन धन सिंह की भूमिका के बारे में साफ और स्पष्ट था। उनका कथन चिकित्सकीय साक्ष्यों से पूरी तरह पुष्ट हुआ। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी इस संबंध में शायद ही कोई लाभ उठा सकता है। दलीप सिंह (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालीन कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 32 के तहत ग्राह्य है। सीआरपीसी की धारा 162 की उपधारा 2 में दिए गए अपवाद को ध्यान में

रखते हुए, ऐसे मृत्युकालीन कथन को तब तक विचार से बाहर रखना बेहतर है, जब तक कि अभियोजन पक्ष अदालत को संतुष्ट नहीं कर देता कि इसे मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी डॉक्टर द्वारा दर्ज क्यों नहीं किया गया। हम ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 32 के प्रावधान, स्वयं, अनिवार्य रूप से यह आवश्यक नहीं करते हैं कि किसी भी नामित या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा मृत्युकालीन कथन दर्ज किया जाना चाहिए। जांच एजेंसी को अधिनियम की धारा 32 सपठित धारा 162 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही मृत्युकालीन कथन दर्ज करते समय कानून के सुस्थापित सिद्धांत और स्थापित प्रथा के अनुसार कार्य करें। यह इसलिए, क्योंकि मृत्युकालीन कथन को अभिलिखित करने के दिशा निर्देश न्यायालयों के न्यायिक निर्णयनों के माध्यम से कानून के विकास के कारण है। कोई आदेश न होने के बावजूद, यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी संदेह या झूठे आरोप की संभावना को खत्म करने के लिए ऐसे कथन मजिस्ट्रेट या डॉक्टर द्वारा दर्ज किये जाएंगे। अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार, व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण या ऐसी परिस्थितियों के बारे में दिया गया कथन ग्राह्य है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई संदेह नहीं है कि मृतक शिव राम का कथन संबंधित डॉक्टर द्वारा कथन देने के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद ही दर्ज किया गया था । मृत्युकालीन कथन का

समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि प्रासंगिक समय पर मौजूद मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार ने किया था। एफआईआर खुद शिव राम के कथन पर दर्ज की गई थी, जिसे हेड कांस्टेबल ने दर्ज किया था, जो संबंधित समय पर ऐसा करने में सक्षम था। हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे कथन की ग्राह्यता में कोई कानूनी कमजोरी नहीं पा सके हैं।

धन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 803

[स्वतंत्र कुमार, जे]

चेरलोपल्ली चेलिमिनाबी साहेद (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि हर मामले में, मृत्युकालीन कथन केवल एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब मृतक के जीवन को कोई गंभीर खतरा न हो तो अधिमानतः कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये जाने चाहिए। उस मामले का निर्णय अपीलार्थी के लिए अधिक सहायक नहीं हो सकता। कांतिलाल (सुप्रा) के मामले में, अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया दूसरा निर्णय, यह न्यायालय मुख्य रूप से उन तथ्यों से चिंतित था जहां कथन देने के लिए मृतक की स्थिति संबंधित व्यक्तियों द्वारा संतोषजनक ढंग से दर्ज नहीं की गई थी। उस मामले में, न्यायालय ने

मृत्युकालीन कथन को ग्राहय माना जिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, उनका वास्तविक घटना के साथ कुछ निकट और निकटतम संबंध होना चाहिए और ऐसी निकटता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। मृत्युकालीन कथन स्वैच्छिक होना चाहिए और प्रेरित नहीं होना चाहिए । निर्माता की शारीरिक और मानसिक फिटनेस को अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत की संतुष्टि के अनुसार साबित करना होगा । उस मामले में, डॉक्टर ने न तो कोई समर्थन किया था और न ही कोई प्रमाणपत्र जारी किया था कि मृतक कथन के लिए फिट था। यहाँ निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। यहां डॉक्टर ने न सिर्फ सर्टिफिकेट जारी किया था बल्कि अपनी राय भी जाहिर की थी जैसा कि एक्स पीएफ 1 से साफ है। इस प्रकार, इस मामले का भी मौजूदा मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

8. साक्ष्य का विश्लेषण:- यह तर्क दिया जाता है कि अपील के तहत न्यायालयों के निर्णयों को रद्द किया जा सकता है क्योंकि उनके निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हैं और विकृत हैं। मृतक के बेटे और उसकी बेटी रचना को गवाह के रूप में परीक्षित नहीं करवाया गया है। किसी भी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं किया गया और किसी भी आरोपी की कोई निश्चित भूमिका नहीं बताई गई, इसलिए आरोपी बरी होने के हकदार थे। कम से कम यह कहा जा सकता है कि यह विवाद बिना किसी योग्यता और तथ्य के है। प्रथम दृष्टया रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि दो भाइयों

के बीच विवाद था। शिव राम की मृत्यु के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार ने अपने विवाद को सुलझा लिया था और अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया था कि प्रवीण और रचना को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया था क्योंकि उन्हें आरोपियों ने मना लिया था। मृतक के दोनों परिवार के सदस्यों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। परिवार के सदस्यों, अन्य गवाहों के कथन, डॉक्टर के कथन और मेडिको लीगल रिपोर्ट को प्रासंगिक मानते हुए, जांच अधिकारी द्वारा यह महसूस किया गया कि परिवार के अन्य दो सदस्यों को परीक्षित नहीं किया जाए। शिव राम का कथन स्पष्ट एवं सन्तोषजनक था। पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित

कर दिया गया। लेकिन, यह अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को दुर्बल नहीं करेगा। न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को न्याय के क्रम को विफल करने की अनुमति नहीं है और यदि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और अभियोजन किसी भी उचित संदेह से परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम है, तो न्यायालय को तथ्य की परवाह किए बिना दोषी को दंडित चाहिए। डॉक्टर के कथन और

उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट प्रदर्श पीए के साथ पढ़ने पर शिव राम का मृत्युकालीन कथन पूरे मामले का खुलासा करता है, जहां मृतक की चोटों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

1. दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर 5 x 2.5 सेमी की त्वचा में अनियमित किनारों और ताजा रक्तस्राव के साथ एक फटा हुआ घाव ।

2. बायीं आंख की भौंह पर 0.5 x 0.25 सेमी गहरा घाव त्वचा में, अनियमित किनारे और ताज़ा रक्तस्राव।

3. बायीं पिन्ना के सामने की ओर 0.50 x 0.25 सेमी गहरा घाव त्वचा में, अनियमित किनारों और ताज़ा रक्तस्राव के साथ।

4. चेहरे के बाईं ओर 1 सेमी एक चोट, बाएं कान के सामने, 5 x 4 सेमी और रंग लाल ।

5. दाहिनी अनामिका की पृष्ठीय सतह पर 2 x 0.25 सेमी त्वचा में गहरा घाव हो गया है और ताजा रक्तस्राव हो रहा है।

6. बाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर एक चोट, जिसका आकार 6 x 2 सेमी और रंग लाल है।

7. दाहिनी स्कैपुलर क्षेत्र पर एक चोट, जिसका आकार 5 x 2 सेमी और रंग लाल है।

8. छाती के पीछे की ओर स्कैपुलर मार्जिन से 1 सेमी नीचे एक चोट इसका माप 5 x 2 सेमी है और यह लाल रंग में था।

9. बायीं कलाई के जोड़ के पिछले हिस्से पर 4 x 3 सेमी का घाव और रंग लाल है।

10. बायीं जांघ के निचले हिस्से में सामने की ओर एक खरोंच, जिसकी माप 4 x 2 सेमी है और रंग लाल है।"

9. इसके विपरीत, शिव राम के पास झूठा कथन देने का कोई कारण नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि लोहे की रॉड से उसके सिर पर बहुत जोरदार वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, वह घटना में प्रत्येक आरोपी की भूमिका निर्दिष्ट करने में सक्षम थापीडब्ल्यू 1 के कथन के अनुसार, मृतक शिव राम की पत्नी और बेटी, ओमकली और बिमला को चोटें आईं, जो अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन करती हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां सिर की चोट घातक साबित हुई जिससे शिव राम की मृत्यु हो गई । जांच अधिकारी सहित अन्य गवाहों के कथनों के अनुसार ओमकली और बिमला को चोटें घटना के दौरान

[स्वतंत्र कुमार, जे]

और शिव राम के घर में लगी हैं। वर्तमान मामले में शिव राम के पास किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से अपने भाइयों और धन सिंह को झूठा फंसाने का कोई अवसर नहीं था। मृतक को लगी चोटें पीडब्लू 1 के कथन से पूरी तरह पुष्ट होती हैं। अदालत के सामने इन गवाहों और मेडिको लीगल रिपोर्ट पर विश्वास न करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था। केवल, क्योंकि मृतक के परिवार के सदस्य न्यायालय के समक्ष गलत कथन देना चाहते थे, इससे अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष ठोस और उचित सबूतों के साथ आरोपी के अपराध को सामने लाने में सक्षम है। इस प्रकार, इन कारणों से, हम आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्षों को चुनौती देने में कोई गुणवता नहीं पाते हैं।

सजा आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत होनी चाहिए न कि आईपीसी की धारा 302 के तहत

10. अपीलकर्ताओं के वकील ने जागृति देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(2009) 14 एससीसी 771] के मामले पर भरोसा जताया है। इस न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि अपराध को कारित करने के लिए इस्तेमाल में ली गयी खुकरी मृतक ने अपने तकिये के नीचे रखी थी,

जबकि वह घर के बाहर बरामदे में सो रहा था और आईपीसी की धारा 302 के अपराध को 304 भाग II आईपीसी में बदलने की अनुमति दी। स्पष्ट है कि आरोपी का मृतक को मारने का कोई आशय नहीं था। गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2009) 15 एससीसी 635] के मामले में, अचानक एक ही लाठी का प्रहार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई और न्यायालय ने अपराध में बदलाव की अनुमति दे दी। अपीलार्थी की ओर से जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनमें बताए गए सिद्धांतों पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ऐसा कोई जकडजामा फॉर्मूला नहीं हो सकता जिसे इस तरह के सभी मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्ति शिव राम को मारने के इरादे से उसके घर गए थे। दरअसल, यह संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद था। वे लाठी-डंडे से लैस होकर गए थे और धन सिंह के पास लोहे की रॉड थी। उसने मृतक के सिर पर एक वार किया था और मृतक को मारने का उसका कोई आशय नहीं था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 323 के तहत मामला शुरू में ही दर्ज किया गया था और हेड कांस्टेबल, राम रतन ने पीडब्ल्यू 1 से परामर्श किया था। जिसने मृतक की हालत स्थिर बताई थी और यह भी प्रमाणित

किया था कि वह कथन देने के लिए मानसिक स्थिति में था, जो अंततः मृत्युकालीन कथन बन गया। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के सामूहिक विश्लेषण और परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का कोई आशय

नहीं था और उसने मारने के आशय से या यह जानते हुए कि इससे मौत होने की संभावना थी, उस पर कोई प्रहार नहीं किया था।

11. इन परिस्थितियों के लिए और उपर्युक्त निर्णयों के अनुरूप, हमारा मानना है कि अपीलार्थी का अपराध आईपीसी की धारा 302 से धारा 304 भाग II में बदला जा सकता है। नतीजतन, हम अपीलार्थी को धारा 304 भाग II के तहत अपराध का दोषी मानते हैं और उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 20,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित करते हैं जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

12. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

डी.जी.

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनुभूति मिश्रा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।